Shri Goray: Sir, I introduce the Bill.

COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL*

(AMENDMENT OF SECTIONS 10, 20, 21 AND 26) BY SHRI S. C. SAMANTA

Shri S. C. Samanta (Tamluk): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Coir Industry Act, 1953.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Coir Industry Act, 1953."

The motion was adopted.

Shri S. C. Samanta: Sir, I introduce the Bill.

ALL INDIA AYURVEDIC UNIVERSITY BILL*

BY SHRI A. T. SARMA.

Shri A. T. Sarma (Chatrapur): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an All India Ayurvedic University under the aegis of the Government of India with a view to resuscitate and encourage the study and growth of the science of Ayurveda in India.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an All India Ayurvedic University under the aegis of the Government of India with a view to resuscitate and encourage the study and growth of the science of Ayurveda in India."

The motion was adopted.

Shri A. T. Sarma: Sir, I introduce the Bill.

CIVIL AVIATION (LICENSING) BILL*

BY SHRI AMJAD ALI

Shri Amjad Ali (Dhubri): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the licensing of certain flying and to repeal relevant sections of the Air Corporations Act, 1953.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the licensing of certain flying and to repeal relevant sections of the Air Corporations Act, 1953."

The motion was adopted.

Shri Amjad Ali: Sir, I introduce the Bill.

14.35 hrs.

RESTORATION OF PLACES OF RELIGIOUS WORSHIP BILL—*contd.*

BY SHRI PRAKASH VIR SHASTRI

Mr. Chairman: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Prakash Vir Shastri on the 1st September 1961:—

"That the Bill to provide for the restoration of places of religious worship in the possession of certain persons or communities to the original rightful owners thereof be taken into consideration."

The time allotted for this Bill is one hour and thirty minutes; time already taken is one hour and 31 minutes. May I know if any other hon. Member wishes to speak?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : सभापति जी, मैं इसके लिए विधिवत् प्रस्ताव

Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II-Section 2 dated 2-12-61.

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

उपस्थित करता हूं कि इस विधेयक के लिए समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए क्योंकि बहुत से मेम्बरों को इस पर बोलना है, मिनिस्टर साहब को बोलना है और मुझे भी उत्तर देना है । तो इसके लिये कम से कम एक घंटा समय बढ़ा दिया जाए ।

Mr. Chairman: What time will the hon. Minister take?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): About fifteen to twenty minutes.

Mr. Chairman: We may extend the time by half an hour. I take it, it is the sense of the House; no formal motion is necessary.

Dr. K. B. Menon (Badagara): Mr. Chairman, Sir, I listened carefully to the speech of Mr. Prakash Vir Shastri. I could not follow it very well, because it was in Hindi. I studied the synopsis of the proceedings. It was a good piece of research, but a bad piece of legislation, ill-timed and ill-conceived. Introduction of such a piece of legislation only deters the progress of integration.

We gained our freedom in 1947. We are still in a formative period and the process of reconstruction and rebuilding has to be done very cautiously and every step must be carefully taken. In the matter of material progress I feel that we have done fairly well; in the matter of social reconstruction our record is not very satisfactory. The riots that we had after freedom have brought in disharmony among religious groups in North India. The S. R. C. Report has brought about discord, rivalry and jealousy among the linguistic groups in the various States. Both these factors have arrested the progress of integration. They have not only arrested the progress of integration; they have also created and thrown out new problems for the young democracy.

Now we have large minorities of Muslims and Christians. Both these are the off-shoots of one of the greatest religions of the world—Judaism. In the new set-up of free India we must understand that these minorities have new aspirations, new ideas and new responsibilities. If the idea of our democracy is to set up a secular State, it should be our aim and endeavour to give these minorities opportunities for self-expression. We accept that the past is certainly with us. The past, however, should not be allowed to prove a liability. It is for us to mould the past in order to make the present more useful. It is a fact that we had the Muslim invasion in 1206 which began with Qutb Ud Din. It is also a fact that many things done in the flush of conquest, if raked up today, will seem very unpleasant. Hindu temples may have been converted to mosques; or mosques may have been converted into Hindu temples. The suggestion of exchange after centuries appears to be very fantastic. What I would suggest is that Hindu temples which were converted into mosques and maintained as mosques today, and the mosques which were converted into Hindu temples and which are maintained as Hindu temples must both be allowed to survive as reminders to the present generation of the sins of our forefathers, Hindus and Muslims. Therefore, to assess responsibility and then to allocate it back, is not, to me, the best thing to do under the present conditions. Integration is a process of slow growth, and in attempting to help integration, we should be sympathetic and we should be understanding and we should be responsible, and then only a national integration can be expected. I therefore oppose the Bill.

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब चेयरमैन साहिब, जहां

तक इस बिल का ताल्लुक है यह ज़ाहिर है कि मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता और हिमायत करना भी मैं अपने लिए एक तौहीन का बायस समझता हूं ।

मैं इस बिल को नहीं समझ सका और यह नहीं समझ सका कि इसे कैसे और किस मकसद के लिए कबूल किया गया है बहस के लिए । मैं इस बिल को बुनियादी तौर पर हिन्दुस्तान की जम्हूरी आईन और हिन्दुस्तान के इस उसूल के कि यहां पर सैक्युलर गवर्नमेंट है और यहां के तमाम लोगों को बिला लिहाज़ मज़हब और मिल्लत के रहने का हक है, उनको अपने अपने मज़हब की आज़ादी है, खिलाफ़ समझता हूं । अगर इस हाउस में कोई ऐसा बिल नहीं आ सकता है जिसका माना यह हो कि लोगों का उस बिल के ज़रिये, मज़हब तबदील कराया जाए क्योंकि मज़हब की तबलीग और जबरन किसी शख्स का मज़हब तबदील करना हमारे आईन के खिलाफ़ है, तो यह जो बिल लाया गया है यह भी नहीं आ सकता । मैं इस बिल में और उस किस्म के बिल में कोई फर्क नहीं समझता हूं ।

अगर आज यह कहा जाता है कि आज से चन्द सौ साल पहले जो अबादतगाहें किसी न किसी वजह से किसी और मज़हब के रंग में तबदील की गई थीं, चाहे वे मस्जिदों की शक्ल अख्तयार कर गई हों, गिरजों की शक्ल अख्तयार कर गई हों, गुरुद्वारों की शक्ल अख्तयार कर गई हों, उनको दुबारा उन मज़हब वालों को लौटा दिया जाए तो यह वही बात होगी कि इस एवान के मेम्बर अली मुहम्मद तारिक जो आज मुसलमान हैं और जिसके आवाजो अजदाद ने जो कि किसी ज़माने में हिन्दू थे डर की वजह से या किसी जब्र के तहत या किसी और वजह से उन्होंने इस्लाम को कबल किया, लिहाज़ा अली मुहम्मद तारिक को हिन्दुस्तान के आज के जम्हूरी आईन में फिर से हिन्दू बना दिया जाए । मैं जो बिल लाया गया है, उस में और दूसरा जो हिन्दू बनाने के बारे में बिल नहीं लाया जा सकता है, उस में कोई फर्क महसूस नहीं करता हूं ।

मुझे इस बात का इंतिहाई अफसोस है और यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि इस बिल को किन बुनियादों पर इस हाउस ने मंजूर किका है, वहस करने के लिए मैं समझता हूं कि इस बिल का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हिन्दुस्तान में फिरका परस्ती को, मज़हबी झगड़ों को अज सिरे नौ जगाया जाए और ऐसी शक्ल दी जाए . . .

श्री बलराज मधोक : आप फिरका-परस्त हैं ?

श्री अ० मु० तारिक : मैं फिरकापरस्त हूं या नहीं, इसेको जानने के लिए वक्त चाहिए, लारीख चाहिये, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मुबालिगा नहीं है कि आनरेबल मैम्बर सौ फी सदी फिरकापरस्त हैं और फिरकापरस्ती उनका मिशन है ।

इन सब बातों के पेशेनजर और इसके पेशेनजर भी कि हम इस मुल्क को बिला लिहाज़ मज़हब और मिल्लत के, आगे ले जाना चाहते हैं, इस मुल्क को तरक्की की मंजिल की तरफ ले जाना चाहते हैं और हाथ में हाथ ले कर एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इस किस्म का बिल यहां पेश करना किसी लिहाज़ से भी काबिले तसव्वुर नहीं है ।

जनाब चैयरमैन साहिब मैं आपकी वसातत से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस बिल को किन बुनियादों पर इस हाउस में मंजूर किया है और हुकूमत ने किन बुनियादों पर!

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : मंजूर नहीं किया है बल्कि यह पेश किया गया है ।

श्री अ० मु० तारिक : पेश तो किया गया है लेकिन पेश करने से पहले हाउस का

[श्री म० मु० तारिक]

सैक्रेटेरिएट ऐसे बिलों की छानबीन करता है और उन्हें इस बहस के लिए मंजूर करता है। मैं समझता हूं कि यह बिल इस काबिल भी नहीं था कि इसको इस हाउस की तरफ से छापा जाता और मुश्तहर किया जाता। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इस किस्म की चीजें जो मुल्क को ग़लत रास्ते पर ले जाने वाली होती हैं, यह सैक्रेटेरिएट या हुकूमत किन बुनियादों पर मंजूर करती है।

इन अलफाज़ के साथ मैं इस बिल की सख्त लफ्ज़ों के साथ मुखालिफत करता हूं और मैं समझता हूं कि इस बिल को इस ऐवान में लाकर इस ऐवान की तौहीन की गई है।

श्री म० ला० द्विवेदी : आनरेबल मेम्बर ने कहा है कि इसको मंजूर किया है। इसे बिल को कहां मंजूर किया गया है, इस पर तो विचार चल रहा है .....

Mr. Chairman: Order, order. We will know it from the hon. Minister, in his speech.

[شری ع - م - طارق: جناب چیرمین صاحب - جہاں تک اس بل کا تعلق ہے یہ ظاہر ہے کہ میں اسکی حمایت نہیں کر سکا اور حمایت کرنا بھی اپنے لئے ایک توہین کا باعث سمجھتا ہوں -

میں اس بل کو نہیں سمجھ سکا اور یہ نہیں سمجھ سکا کہ اسے کیسے اور کس مقصد کے لئے قبول کیا گیا ہے بحث کے لئے - میں اس بل کو بنیادی طور پر ہندوستان کے جمہوری آئین اور ہندوستان کے اس اصول کے کہ یہاں پر سیکولر گورنمنٹ ہے اور یہاں کے تمام لوگوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت کے رہنے کا حق ہے - انکو اپنے اپنے مذہب کی آزادی ہے - خلاف سمجھتا ہوں - اگر اس ہاؤس میں کوئی ایسا بل نہیں آ سکا ہے جس کے معنی یہ ہو کہ لوگوں کا اس بل کے ذریعے مذہب تبدیل کرایا جائے کیونکہ مذہب کی تبلیغ اور جبراً کسی شخص کا مذہب تبدیل کرنا ہمارے آئین کے خلاف ہے تو یہ جو بل لایا گیا ہے یہ بھی نہیں آ سکتا تھا - میں اس بل میں اور اس قسم کے بل میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہوں -

اگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ آج سے چند سو سال پہلے جو عبادت گاہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی اور مذہب کے رنگ میں تبدیل کی گئی تھیں چاہے وہ مسجدوں کی شکل اختیار کر گئی ہوں - گرجوں کی شکل اختیار کر گئی ہوں - گرودواروں کی شکل اختیار کر گئی ہوں - انکو دوبارہ ان مذہب والوں کو لوٹا دیا جائے تو یہ وہی بات ہوگی کہ اس ایوان کے ممبر علی محمد طارق جو آج مسلمان ہیں اور جس کے آبا و اجداد جو کہ کسی زمانے میں ہندو تھے اور ڈر کی وجہ سے یا کسی جبر کے تحت یا کسی اور وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا لہذا علی محمد طارق کو

ہیں - اس قسم کا بل یہاں پیش کرنا کسی لحاظ سے بھی قابل تصور نہیں ہے -

جناب چیرمین صاحب - میں آپکی وساطت سے سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس بل کو کن بنیادوں پر اس ہاؤس نے منظور کیا ہے اور حکومت نے کن بنیادوں پر ....

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : मंजूर नहीं किया है बल्कि यह पेश किया गया है

شری ع - م - طارق : پیش کیا گیا ہے لیکن پیش کرنے سے پہلے ہاوس کا سیکریٹیریٹ ایسے بلوں کی چھان بین کرتا ہے اور انہیں بحث کے لئے منظور کرتا ہے - میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو ہاوس کی طرف سے چھاپا جاتا اور مشتہر کیا جاتا - میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں جو ملک کو غلط راستے پر لے جانے والی ہوتی ہیں یہ سیکریٹیریٹ حکومت کی بنیادوں پر منظور کرتی رہے -

ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی سخت لفظوں کے ساتھ مخالفت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کو اس ایوان میں لا کر اس ایوان کی توہین کی گئی ہے -]

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): Mr. Chairman, Sir, my hon. friend,

ہندوستان کے آج کے جمہوری آئین میں پھر سے ہندو بنا دیا جائے - میں جو بل لایا گیا ہے اس میں اور دوسرا جو ہندو بنانے کے بارے میں، بل نہیں لایا جا سکتا ہے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا ہوں -

مجھے اس انتہائی افسوس ہے اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اس بل کو کن بنیادوں پر اس ہاؤس نے منظور کیا ہے بحث کرنے کے لئے - میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہندوستان میں فرقہ پرستی کو - مذہبی جھگڑوں کو ازسرنو جگایا جائے اور ایسی شکل دی جائے...

श्री बलराज मधोक : आप फिरका परस्त हैं?

شری ع - م - طارق : میں فرقہ پرست ہوں یا نہیں اس کو جاننے کے لئے وقت چاہئے - تاریخ چاہئے - لیکن اس میں بالکل بھی مبالغہ نہیں ہے کہ آنریبل ممبر سو فیصدی فرقہ پرست ہیں اور فرقہ پرستی انکا مشن ہے -

ان سب باتوں کے پیش نظر اور اس کے پیش نظر بھی کہ ہم اس ملک کو بلا لحاظ مذہب اور ملت کے آگے لے جانا چاہتے ہیں - اس ملک کو ترقی کی منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے

[Shri Datar]

Shri Prakash Vir Shastri, has brought forward this Bill, and, as has been made clear from the debate during the last time as also today, this is a highly controversial and also an undesirable piece of legislation that he proposes to Parliament to pass. I may point out that it is perfectly possible to understand what the hon. Member has in view, but the question is whether, at this stage, it would be possible to rewrite or rather to unwrite the whole history. That is the question that we have to take into account.

Before I deal with the merits of this Bill, I should like to point out to my hon. friend a number of difficulties,—constitutional difficulties—that come in the way. The hon. Mover desires that the State Governments should take possession of the places of worship, naturally with all the property attached to them and thereafter to transfer them, according to him, to that person or that community which owkned those particular religious institution formerly. That would take us through a course of research so far as the former istory is concerned. Apart from that, the question is whether, under the Constitution, it is open to the Government to take possession, by force, of certain properties.

My hon. friend has been careful enough not to deal with the question of compensation which aspect also has to be taken into account. In all such cases, either we take the property by private force, if that is possible, and then we subject ourselves to the liabilities to be imposed by a court of law, or . . .

Shri Bal Raj Madhok (New Delhi): Compensation can be paid.

Shri Datar: If the Government also proposes to use its sanctions, that is, to take possession of the property under a piece of legislation that the hon. Member wants this House to pass, what will it lead to? That is a question which has to be considered very carefully, firstly, from the constitutional point of view. Therefore, I may submit that this intended piece of legislation is, to a large extent, expropriatory in character.

Also, another concrete or great principle has been unfortunately violated by my hon. friend, perhaps with good intentions. I am not prepared to impeach his good intentions. That is, a question arises as to whether the title over certain religious places and lands and other properties can be enquired into at all. There is no provision even for enquiry. Assuming such an enquiry has to be made, it has to be done only by the judiciary and not by the executive. What my hon. friend desires us to do is this: all places of religious worship which have been in the past converted, have to be found out and enquired into. This "past" is an indefinite past; perhaps it is the hoary past. Who are to determine what is the past? Who are to determine when the property was taken possession of from one person or one community and made over to another? Therefore, the particular tribunal that can go into this question is naturally a civil judicial tribunal, but the hon. Member desires that the property should be taken possession of forcibly. The words "forcibly taking possession" have been mentioned. As an eminent lawyer, you know that after a certain time, the law of prescription operates. Taking the worst case, under the civil law, if I had been in adverse possession of a particular piece of property for 12 long years, in spite of my adverse act, in spite of my so-called illegal or immoral act, under the law of limitation, I become owner of the property. That may be right or wrong, but so far as the ethical aspect is concerned, we have got the law of prescription or limitation. It says that if a man is owner of a property, he should be vigilant and protect the property from going into the possession of another. It is on this ground that the civil law has laid down that there are certain periods during which if there are laches on

your part and if there is a positive act of an adverse nature on the part f the other, you lose possession of the property.

Apart from the secular nature of the Government, it is perfectly possible that certain forcible dispossessions might have taken place in the past. Assuming that, what is the way in which that particular alleged forcible dispossession has to be relieved against? There are two or three remedies. There are different laws applicable to public institutions and a larger limitation period is allowed to them under section 10 of the Limitation Act.

It is open to an aggrieved person or community to approach the civil court and take necessary action. If there are public trusts, then the law of limitation cannot take operation in the way in which it can do in respect of, say, implied trusts or private trusts. I am not entering into the question of law in general, but my point is whether we might clothe the State Governments with such summary powers. It should be noted very clearly that the Constitution has been based upon certain fundamental principles. The House is aware that taking possession of a property has been regulated by certain provisions laid down in the Constitution. Under these circumstances, is it open to us to pass a law of a summary nature?

Assuming for the sake of argument that 2000 years ago, some property was taken possession of I am not entering into the question of a particular community—an hon. Member from Punjab has pointed out that there are places where mosques have been taken possession of by other communities and they are being used for their own religious purposes. We need not enter into the question of that community or this community. If force has been used and possession has been taken from a person or community, why did that person or community remain silent when the civil courts were there to adjudicate in their favour? This point has to be fully taken into account before we proceed with the merits or otherwise of this particular piece of legislation.

The hon. Member has unfortunately used very wide words in the clauses. He says:

> "All places of religious worship, which have in the past been forcibly taken possession of by persons professing different faiths, shall be liable to be restored."

As some hon. Member pointed out, even within the orbit of one religion itself, there are different sects and different temples. When I was looking into the proceedings, I saw that a reference was made to *Saivite* temples and *Vaishnavite* temples. They are both within the fold of Hinduism. Assuming that one particular sub-community has taken possession of a temple and has been in possession thereof, because the law has to protect the possession after a number of years, in such a case would it be desirable, possible or constitutional to allow the summary taking possession of such a property by the executive of a State Government, as my friend desires?

My first objection in principle is this. Under the civil law of the land, we have got courts of law which will go into questions of a civil nature and settle the matter in respect of private property or public property, in respect of which my friend has made no distinction. So, it would be entirely wrong to have a sweeping Bill covering all private religious places or public religious institutions. Technically, public religious institutions come under Schedule III, which is in the Concurrent List. But public religious institutions have got oftentimes extensive properties. Then, they would come under the State List. In any case, this is not a matter on which the Parliament can legislate, so far as the jurisdiction of the State Governments is concerned.

In any case, as I pointed out, in respect of concurrent jurisdiction, the

[Shri Datar]

practice of Parliament and the Government of India is not to pass any legislation unless we have got the views of the State Governments before us, because this is a matter which mostly concerns them. There are 15 States and this would affect all the 15 States. The Government of India's jurisdiction is confined to a few territories under their direct administration. So, my hon. friend's bill suffers from a number of highly constitutional difficulties.

Coming to the question of merits, as to whether it is worthwhile passing such a piece of legislation, this is likely to lead to what he himself has stated so far as the other context is concerned a sense of irritation. A sense of irritation is either present or past. For example, if 2,000 years ago a temple has been taken possession of by another community—Christian or Muslim—or *vice versa*, can it be stated today that after 2,000 years there is a sense of irritation? (*Interruptions*). My hon. friend can wait. I can understand the sense of irritation, but this will be counter-balanced by a new sense of irritation. Assuming I belong to another religion and I am in possession of a temple for 200 years and if my possession is to be summarily taken away from me, as the hon. Member has suggested, that will lead to not only a sense of personal irritation, but a sense of frustration, so far as my valuable rights are concerned. Whatever they might be, my rights have been perfected by the passage of time.

Under these circumstances, though the hon. Member has made reference to a sense of irritation, that sense of irritation is likely to be unreal and is likely to have passed and a new sense of irritation is likely to lead even to disturbances. He should understand that. After all, we require a peaceful society and a peaceful solution of all questions—personal questions, family questions, social questions, national and even international questions. That is what we have been after. Under these circumstances, it would not be proper, in my opinion, to pass such a sweeping piece of legislation as the hon. Member desires.

15 hrs.

He does not stop there. He says that the State Government ought to make a declaration that so and so property was in the dim past in the possession of a particular community and that thereafter, perhaps after a number of centuries it has remained with the followers of another religion. Now, it has remained with them for some time. In spite of all the research that the hon. Member has made into the history of certain temples or religious institutions, we have to understand the facts as they are. Apart from the question as to whether the Government is a secular government or otherwise, the question remains whether after allowing a thing to remain as it is for a number of not merely decades but centuries, it would be proper, whether it would be advisable, whether it would be desirable to take such an action or to clothe the State Government with such wide powers.

So far as the governments in the States or the government at the centre are concerned, we are a secular government. The government have no religion at all so far as the structure of the governmental machinery is concerned. Under the circumstances, will it be proper—I would put it to my hon. friend—to clothe the present government, in their present structure and their character, with such wide powers so far as the religious institutions are concerned? I can understand a court of law entering into the question because what they do there is that they adjudicate upon civil rights. But here the question arises whether it would be proper to give all these wide powers to a State Government.

The hon. Member has, unfortunately, not followed one of the principles of natural law. When an order has to be passed, as the House knows,

the first principle is that if an order has to be passed against a particular person in the first place he ought to be given a hearing; and, secondly, after the adverse order has been passed, he ought to have some remedy either by way of appeal or by way of revision. These are inherent in the principles of natural justice. Unfortunately, the hon. Member has not even looked into that aspect of the matter at all.

Then, he does not stop there. He says that after the State Government ultimately declares that a particular place is a place of religious worship—I have pointed out the implications—all the properties attached to it also will have to be removed from the possession of one person and handed over to another person. That question also will naturally arise. Further, what the hon. Member wants to do is that in case any particular order has been passed by the State Government then certain penal consequences also should follow, penal consequences as pointed out in clause 5 of the Bill. It says:

> "Whoever intentionally obstructs any person or community in the exercise of the rights conferred by this Act shall be punishable with imprisonment which may extend to one year, or with fine or with both."

Therefore, we have got a penal provision also.

Therefore, I am afraid my hon. friend, whatever his particular motives may be, which we can understand though we might not appreciate, has brought forward a Bill which, as I have stated is highly controversial, is undersirable in its contents, and I am hoping that the hon. Member will not persist in allowing this Bill to be considered by the House and force a division.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, संसद के पिछले अधिवेशन में जब इस विधेयक को मैं ने उपस्थित किया था तो मेरे मस्तिष्क में देश का वह वातावरण कार्य कर रहा था जिस को आज कल के हमारे नेता भावात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं और उसी पृष्ठभूमि में मैं ने इस विधेयक को संसद के सामने उपस्थित भी किया था ।

इस विधेयक को उपस्थित करते समय मैं ने सबसे पहले जानने का यत्न किया कि हमारे देश में हिन्दुओं के अतिरिक्त जो दूसरे सम्प्रदाय हैं उनके कुछ धर्म मन्दिर तो इस प्रकार के नहीं हैं कि जिनको बलात् किसी ने अपने अधिकार में करके किसी दुसरे रूप में परिवर्तित कर दिया हो । मैंने भारत सरकार से इस संबंध में जानकारी चाही और हमारे पुनर्वास मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान बनने के पश्चात् जो मस्जिदें और मजार उन लोगों के जो पाकिस्तान चले गये थे पंजाब और दुसरे स्थानों में रह गए थे उनमें अधिकांश उनको वापस किए जा चुके हैं । उन्होंने उन स्थानों की संख्या भी बतलायी । उन्होंने बतलाया कि इस प्रकार के २०,६६६ धर्म स्थान हमने उनको वापस किए हैं । १६ के संबंध में हमारे पुनर्वास मंत्री ने बताया कि बंगाल में अभी कुछ ऐसी मस्जिदें शेष हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी बनने को तैयार नहीं हैं इसलिए उनको अभी तक किसी को नहीं दिया जा सका उनका कोई उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो उनको भी वापिस कर दिया जाएगा । अपने विधेयक को उपस्थित करते समय मैं ने सरकार को इसके लिए धन्वाद दिया था कि उसने देश में भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिए एक अनुकल निर्णय लिया । उसी के साथ साथ मैं ने तस्वीर का दूसरा पहलू भी सदन के सामने उपस्थित किया था । मैंने निवेदन किया था कि जब आपने इतनी बड़ी संख्या में उन धर्मस्थानों को जिनकें दूसरों के हाथ में जाने से उस धर्म के अनुयायियों के हृदय को चोट पहुंचती वापस कर दिया है, तो यह भी आवश्यक

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

है कि दुसरे धर्म के उन धर्म स्थानों को भी जिनको भूत काल में दूसरे धर्म वालों न परिवर्तित कर लिया हो वापस कर दिया जाए । और मैंने इसके लिए कुछ उदाहरण भी दिए थे जिनमें एक मथुरा का कृष्ण जन्म मन्दिर है जिस पर आज एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है । जब कोई यात्री मथुरा के स्टेशन पर धार्मिक भावना लेकर जाता है और जानना चाहता है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था तो उस स्थान पर इस बड़ी मस्जिद को देखकर उसके हृदय में चोट पहुंचती है ।

इसी प्रकार जब कोई तीर्थ यात्री अयोध्या जाकर भगवान राम का जन्म स्थान देखना चाहता है तो वहां भी एक मस्जिद को खड़ी देख कर उसके मन को ठेस लगती है ।

अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि यह बहुत साधारण सी चीज है इसके लिए इतना बड़ा वातावरण तैयार नहीं करना चाहिए मैं उनसे उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि अगर यरूसलम में जहां महात्मा ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस स्थान पर जो गिरजाघर बना हुआ है उसको कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने अधिकार में लेकर उसके स्थान पर अपने धर्म के अनुसार कोई दूसरा धर्म मन्दिर बनवा दे तो जिस तरह से ईसाई धर्म के अनयायियों को चोट पहुंचेगी उसी तरह हिन्दुओं को इन मन्दिरों के परिवर्तन के कारण चोट पहुंचती है । यदि यरूसलम के गिरजा घर के बजाए किसी दूसरे गिरजाघर को परिवर्तिन कर दिया जाए तो उस धर्म के अनुयायियों को उतनी चोट नहीं पहुंचेगी जितनी कि यरूसलम के गिरजाघर के परिवर्तन से पहुंचेगी क्योंकि उस स्थान पर महात्मा ईसा का जन्म हुआ था । इस प्रकार राम और कृष्ण को इस देश की जनता का एक बहुत बड़ा भाग अपने महापुरूष मानता है और अगर उन स्थानों पर दूसरे मतों के इबादतगाह या मस्जिदें बनी हों तो देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के हृदय को ठेस लगती है । और इसी दृष्टि से मैं न चाहा था कि हमारी सरकार जो कि एक धर्म निरपेक्ष सरकार है और किसी के धार्मिक अधिकारी का हनन नहीं होने देना चाहती और सब के धार्मिक अधिकारों को संरक्षण देती है हमारे धर्म स्थानों को वापस दिलवाए । जहां हमारा यह शासन आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सभी दृष्टियों से देश के लोगों को संरक्षण देता है वहां एक धर्मनिरपेक्ष शासन होने के कारण उसका यह नैतिक कर्तव्य है कि देश में लोगों को धार्मिक संरक्षण दे और इस प्रकार भावात्मक एकता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करे ।

इसी लिए मैं न चाहा था कि इस विधेयक के द्वारा इस समस्या का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान हो जाए । इस बात का मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं । पिछली बार इस विधेयक को उपस्थित करते समय मैं ने कहा था कि कनिंघम ने अपनी कलम से लिखा है कि अकेले अयोध्या के राम जन्म मन्दिर को पुन: मन्दिर के रूप में परिवर्तित करने के लिए ७४,००० आदमियों को बालिदान देना पड़ा था । यह मन्दिर तीन बार बना और तीन बार बिगाड़ा गया । मैं यह विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रश्न का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ तो देश में धीरे धीरे ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा कि फिर इसका दुसरे ढंग से समाधान किया जाए । लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों में यही अच्छा है कि इसका समाधान शान्तिपूर्ण तरीके से किया जाता मुझे इन शब्दों के कहने की आज्ञा दीजिए ।

मैं अपने संक्षिप्त वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए बड़ी नम्रता से कहना

चाहता हूं कि हमारी सरकार की यह आदत पड़ती जा रही है कि अगर हिन्दुओं के विपरीत कोई बात कही जाती है तो उसको अल्पसंख्यकों के संरक्षण और अल्पसंख्यक जाति को सुविधा देने के नाम पर तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन अगर कोई बात इस विशाल सम्प्रदाय के संरक्षण की आती है तो उसको साम्प्रदायिक और देश के अन्दर खराब वातावरण पैदा करने वाली कह कर पीछे डाल दिया जाता है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की जनता अब इसको ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकेगी इसलिए मेरा बहुत नम्रता के साथ अनुरोध है कि जो विधेयक मैं ने उपस्थित किया है यह बहुत न्यायसंगत विधेयक है इसको स्वीकार किया जाय । इसमें मैं ने किसी धर्म विशेष केलिए यह नहीं चाहा कि उसको कोई विशेष सुविधा दी जाए । मैं ने उस समय कहा था कि अगर मुसलमानों की कुछ मस्जिदें हिन्दुओं के कब्जे में हैं तो वे उनको वापिस दे दी जाएं और इसी तरह से ईसाईयों के कुछ धर्म-स्थान दूसरों के अधिकार में चले गए हों, तो वे भी उनको वापिस कर दिये जायें । यही बात मैंने दूसरे धर्मों के बारे में कही थी । जब मैं उनके लिए मांग कर सकता हूं तो म इसके लिए भी दृढ़तापूर्वक मांग कर सकता हूं कि हिन्दुओं के कोई धर्म-स्थान अगर दूसरों के अधिकार में हैं जिससे उस धर्म के अनुयायियों को चोट लगती हैं, तो वे भी वापिस कर दिये जायें । यह बड़ा संगत विधेयक है और और मैं समझता हूं कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए ।

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill to provide for the restoration of places of religious worship in the possession of certain persons or communities to the original rightful owners thereof be taken into consideration."

The motion was negatived.

15.11 hrs.

DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF SECTION 14) BY SHRI TANGAMANI

Mr. Chairman: The House will now take up the consideration of the Delhi Rent Control (Amendment) Bill.

Shri Tangamani (Madurai): Mr. Chairman, I beg to move:

"That the Bill to amend the Delhi Rent Control Act, 1958, be taken into consideration."

In the Statement of Objects and Reasons I have briefly explained the purpose for which I have brought forward this Bill. It reads:

"Under the existing instructions relating to the allotment of Government accommodation, a Government servant, who has been allotted Government quarter, is liable to eviction or in default to pay the maximum penal rent as soon as he becomes the owner of the house. On the other hand, under the Delhi Rent Control Act, 1958 (No. 59 of 1958) a landlord who has acquired a house by transfer and requires it for his *bona fide* residence, cannot file an application for the eviction of a tenant unless a period of 5 years has elapsed from the date of acquiring the house. This anomalous position of law has resulted in hardship in a number of cases. Hence this amending Bill."

The purpose is a very limited one. I wanted to find out the exact position from the hon. Minister of Home